RAJYA SABHA

Friday, the 1st August, 1981/10 Sravana 1908 (Saka)

The House met at 11 of the Clock. **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*221. [*The Questioner (Shri D. B. Chandra Gowda) was absent. For answer vide cols:* **infra**]

Houses for Delhi's Population

*222. SHRI PRAMOD MAHAJAN†
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the average increase in Delhi's population each year,

(b) what is the backlog of houses required by Delhi's population at present and by how much it is likely to increase each year ;

(c) what is the budgetary provision for this purpose this year and by how much backlog is expected to be cleared in this year ; and

(d) by when the entire backlog is planned to be wiped out ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) the estimated increase in Delhi's population is about 3 lakh persons per year.

(b) The estimate of housing shortage at the beginning of the 7th Plan was placed at about 3.8 lakh dwelling units The additional housing requirement is estimated to be about 60,000 dwelling units per year.

(c) A provision of Rs. 438,13 crores has been made in the DDAs' Budget Estimates for 1986-87 for construction of houses. The DDA has a backlog of 1,61,679 registrants. As against this, it has a plan to allot 51,354 dwelling units this year under the various housing schemes .

(d) No time-bound programme for the clearance of the bac[illegible] be given at this stage.

† The Question was actually asked on the floor the House by Shri Pramod Mahojan.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक वर्ष में एक लाख मकान बनाने की घोषणा की थी, लेकिन मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि इस वर्ष केवल 51,354 मकान बन रहे हैं। इस सब से यह साफ हो जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह घोषणा पूर्णतः असत्य है तथा दिल्ली के नागरिकों को फंसाने के हेतु से की गई है। मैं मंत्री महोदय को इस विषय में यह बताना चाहूंगा कि उनके उत्तर से यह पता चलता है कि 3 लाख 80 हजार मकानों की आज कमी है और हर साल इसमें 60 हजार की कमी बढ़ती जाएगी। इस हिसाब से दिल्ली विकास प्राधिकरण आज 1 लाख 10 हजार घर नहीं दे पा रहा है। इस हिसाब को देखते हुए दिल्ली के नागरिकों को, हर व्यक्ति को, घर मिले, इस दृष्टि से क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का बजट बढ़ाने की कोई योजना है, कोई क्रेश प्रोग्राम सरकार की तरफ से.... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: You are delivering a lecture. Please put the question.

श्री प्रमोद महाजन : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के बजट को बढ़ाते हुए कोई क्रेश प्रोग्राम लेकर इस कमी को दूर करने के लिए क्या सरकार के मन में कोई योजना है? यदि हां, तो उसके बारे में मंत्री महोदय बताने की कृपा करें?

श्री अब्दुल गफूर : सरकार के मन में तो बहुत-सी योजनाएं हैं। लेकिन सरकार को जो डिफिकल्टीज हैं उनको सब लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पर

सन 1982–83 में हमने 120 करोड़ रुपया खर्च किया। सन 1983–84 में कुछ कम किया, 114 करोड़ रुपया खर्च किया। उसके बाद यह बढ़ा और 118 करोड़ रुपया खर्च किया। सन् 1985–86 में 197 करोड़ खर्च हुआ और सन 1986 में 467 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। उन्होंने यह पढ़कर बता दिया है। यहां पर 438 करोड़ लिखा है, ये 467 करोड़ बता रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : आपको यह बताया है, आप इसको अच्छी तरह से सम लीजिये। आपको इस बारे में मालम नहीं है। डी०डी०ए० ने यह बजट बनाया है। हम इस बजट को ज्यादा भी बना सकते हैं। लेकिन आप हमारी मजबूरी भी देखिये। रुपया खुद गवर्नमेंट नहीं देती है। एशियाड विलेज पर हमने 120 करोड़ रुपये खर्च किये। हमने कहा कि हमारा रुपया दीजिये, लेकिन वह नहीं मिला। फिर उसके बाद रिसेटलमेन्ट कालोनीज हैं। हर साल चार पांच सौ करोड़ रुपया खर्च होता है। अब यह सब मिलाकर 108 करोड़ रुपया हो गया। डी०डी०ए० कोई ऐसा विभाग नहीं है जो वसूल कर ले। न इसके लिये न कोई बजट में जैसा होता है कि एजकेशन में खर्चा होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर कह देंगे कि कर दीजिये। डी०डी०ए० में इतना खर्चा होगा तो कहां से आयेगा। हम ही सब चीज खर्च करेंगे, हम ही रुपया जमा करायेंगे, जमीन एक्वायर करेंगे और इसकी कुछ कीमत कमर्शियल लोगों को प्लाट बेचकर अपना कुछ काम चलाते हैं। अगर सब लोग कोशिश करें तो सब हल हो सकता है।

SHRI PRAMOD MAHAJAN : I will ask second supplementary.

MR. CHAIRMAN : You have already put two supplementaries. All right. You can put one more question.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार की ओर से डी० डी० ए० का 120 करोड़ रुपया आना है। इसका जिकर उन्होंने किया। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के नागरिकों का जहां तक सवाल है उस सवाल में सरकार और डी०डी०ए० शामिल हैं। सरकार ने एशियाड के लिय जो मकान बनाए थे, स्टेडियम बनाए थे उस पैसे को अगर सरकार ने नहीं दिया तो उसके लिये दिल्ली के नागरिक जिम्मेदार हो नहीं सकते। यह आपका आपसी मामला है। इसके लिए आपको मुझ से नहीं आपको उनसे सहयोग मांगना चाहिए। इसलिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या डी० डी० ए० की ओर से, इस 120 करोड़ रुपये के लिये जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से आना बाकी है अगर वह पैसा वक्त पर न दिया जाय तो क्या केन्द्र सरकार के द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायेगा ?

श्री अब्दुल गफूर : हम सोचते हैं क्या कार्यवाही करेंगे। 150 मकान हमने जनरल पूल में प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने से दिये हैं। लेकिन वे लोग कहते हैं कि अगले बजट में प्रावधान होगा। हमने कहा ठीक है 5–6 महीने, वेट कर लेंगे। दूसरे 50 फ्लेट इसमें, डाइनिंग हाल मिलाकर ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें दे दीजिये हमने कहा ले लीजिये और रुपया दे दीजिये। बाकी 380 फ्लेट्स के बारे में हम लोगों ने डिसीजन किया है कि सेल बाई आक्शन। हमने इसको एडवर्टाइज कर दिया है 10 फ्लैट बेचने के लिये दिया है और उनको बेचने जा रहे हैं जिसको खरीदना होगा खरीदेगा। हम तो यह सजा दी जा रही है। दूसरी चीज और भी है स्टेडियम के मुतालिक। नहीं खरीदेंगे तो हम उसको प्राइवेट पार्टी को बेच देंगे और उसका इंतजाम करेंगे। हमको लाखों रुपया इसके मेन्टनेंस पर खर्च करना पड़ता है, इसके अलावा

देना पड़ता है। इसके अलावा हम आपको भी मकानात देते हैं। आप लोग भी डी० डी० ए० के मकानों पर आकर रहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, साकी के मन में क्या है यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि पैमाने में क्या है।

कई माननीय सदस्य : सवाल यह है कि पैमाने में क्या है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, दिल्ली में आबादी के हिसाब से मकान नहीं बन रहे हैं और जो बन रहे हैं वे पुख्ता नहीं हैं। डी०डी०ए० ने ऐसे मकान बनाये हैं जिनकी नींव नहीं थी। डी०डी०ए० भ्रष्टाचार में डूबी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या डी०डी०ए० को भंग करके आप कोई नयी अथारिटी, नया प्राधिकरण बनाने पर विचार करेंगे जो दिल्ली में मकानों के निर्माण का काम क्रैश बैसिस पर करे।

श्री अब्दुल गफूर : वाजपेयी जी आपके आने के पहले हम लोगों ने सोचा था कि हिन्दुस्तान में जो अभी तक मकान बन रहे हैं वे ब्रिक बाई ब्रिक, एक ईटा के ऊपर दूसरा ईटा रखकर के हैं। पिछली लड़ाई में, जब वर्ल्ड वार हुआ था, जर्मनी में, हंगरी में, फ्रांस में कहीं 90 प्रतिशत, कहीं 80 प्रतिशत मकान जमीन के बराबर कर दिये थे। लेकिन साथ ही यह भी पता चला कि दो साल के अन्दर सबको बना लिया था। तो हम लोगों ने भी सोचा कि यह कैसे किया जाय। जो आपकी नीयत है मेरी उससे अच्छी तरह से सहमति है और मैं खुद परेशान भी हूं। तो हम लोगों ने यह किया कि उसके टेंडर निकाले और उस टेंडर में यह कहा कि बेस्ट जिस मुल्क का प्रीफेब्रिकेशन है उनसे टेंडर मंगाये जाए। जिन लोगों ने टेंडर दिया है अभी उनके टेंडर फाइनलाइज नहीं हुये हैं। उन टेंडरों के जरिये अगर वह होगा, हमने भी अपनी आंखों से जाकर मकानात देखे हैं...यह प्रिफेब्रीकेटेड मकान कैसा बनता है, उसको देख कर तबीयत खुश हो जाती है। एक जगह मैं गया... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बारसीलोना में...

श्री अब्दुल गफूर : उसके बारे में मैं आपको बताता हूं आप लोग भी जरा हमदर्दी कीजियेगा तो शायद हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वहां पर उस कंट्री के हाऊसिंग बोर्ड वाले हम को दिखाने के लिये ले गये और उसने कहा कि देखिये यह पहली स्टेज में हम लोगों ने बनाया है वार के बाद और तीन महीने तक हमने रिसर्च किया है कि लोगों को रोशनी मिलती है, हवा आती है, लड़कों को पढ़ने के लिये कैसी जगह है। तो उन्होंने उसमें डिफेक्ट्स बताए। तीन महीने के बाद हम लोगों का दूसरा फेज चला और इस प्रकार से उसमें सब डिफेक्ट्स को दूर किया गया। उसके बाद तीसरा फेज में ले चले। फिर उन्होंने कहा आपको चौथी जगह ले चलते हैं जहां हम लोगों ने बनाया है, वहां ले गये। वहां पर दो रूम ड्राइंग-डाइनिंग देखा क्या खूबसूरत बना है वाजपेयी जी अगर चलिये तो तबीयत खुश हो जायेगी (व्यवधान) दिल में तो सब अरमान हैं लेकिन जब देखते हैं रुपये की तरफ लोगों की तरफ से तो जरा सी परेशानी होती है। ख्वाहिश हम लोगों की बहुत है कि हम भी उस टेक्नोलोजी को अपने मुल्क में ले आए... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, you must give pointed answers.

श्री अब्दुल गफूर : यह इसलिये कह रहा हूं कि फरदर सप्लीमेंटरी नहीं पूछें। ठीक है, नहीं कहता हूं।

MR. CHAIRMAN: No.

SHRI VIRENDRA VERMA: Pointed question, pointed answer.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Shanti Tyagi.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What about my supplementary, Sir ?

MR. CHAIRMAN: He is supposed to have answered your supplementary.

श्री शान्ति त्यागी : सभापति जी, मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और यह लगातार बढ़ती ही जाएगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। नेशनल केपिटल रीजन योजना जो आपने बनाई है उसमें इस क्षेत्र के कुछ शहरों में गाजियाबाद और मेरठ में भी दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी के लिये कुछ आवासीय मकान बनाने की क्या कोई योजना है, यदि है तो कहां-कहां पर यह मकान बनाये जाएंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : मेरे पास यह सब नहीं है, इसमें 7-8 शहर लिये गये हैं। वहां मकान बन भी रहे हैं लेकिन यह योजना है कि दिल्ली की आबादी को किस तरह से आगे न बढ़ने दिया जाए और जो इतनी आबादी बढ़ रही है उसमें कमी कैसे की जाए, यह भी है। हमारे चेयरमैन साहब इजाजत नहीं देंगे नहीं तो हम उसको भी बता देते।

MR. CHAIRMAN: Very Good

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सेवंथ फाइव ईयर प्लान के प्रारंभ में तीन लाख अस्सी हजार मकानों की दिल्ली में आवश्यकता है और 60 हजार मकान प्रतिवर्ष उनकी आवश्यकता है तो जाहिर है कि जो आदमी दिल्ली में आते हैं नये तथा जो पुराने हैं उनको मकानों की आवश्यकता है और पैसे की भी उनको आवश्यकता है जिसके लिये मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि एक तरफ बसाने के लिये 60 हजार मकान बनाने हैं और किसानों को जमीन के बारे में क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इन्होंने लोगों को बसाने के लिये किसानों की जमीन दो ये, तीन रुपये प्रति मीटर के ऊपर थ्री-अर्थ प्राइस पर ली जाती है और 240 रुपये प्रति मीटर डवलपमेंट चार्जेज खर्च करके 50 हजार रुपये प्रति मीटर पर उसको ऑक्शन किया जाता है। यदि यह सही है तो क्या दोनों तरफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है और इसे रोकने में सरकार क्या करेगी ?

श्री अब्दुल गफूर : उसमें डवलपमेंट वगैरह में खर्च हो जाता है थोड़ा सा उसी को... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा: यह थोड़ा, थोड़े ही है, मान्यवर। दो-तीन रुपये प्रति मीटर के हिसाब से किसान की जमीन ली जाती है और उसको 50 हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से ब्लैक मनी के लिये ब्लैक मार्कीटियर्स को बेचा जाता है।

श्री अब्दुल गफूर : ब्लैक मार्किट नहीं है वह तो ओपन मार्किट है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : लेकिन ब्लैक मनी का प्रयोग होता है।

श्री अब्दुल गफफूर : दूसरी चीज यह है कि सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : फिर किसानों को क्यों उजाड़ रहे हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : सारी फेसिलिटीज लोगों को मिलती है जैसे इलैक्ट्रिक, रोड्ज, सीवरेज, सब बनाने में रुपया खर्च होता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: 240 रुपये प्रति मीटर आप खर्च करते हैं और 50 हजार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बेचते हैं।

Mr. Chairman : Yes Mr. Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI : The Minister has said that the difficulties of his Ministry seem to be of finance. But, Sir, in Delhi, as you know colonies like trans-Yamuna colonies etc. require an urgent effort to put up houses, small houses, not these Asiad houses, which is a luxury; they are not interested in that. So has the Government got any plan for slum dwellers for colonies which are already on the ground and for middle class people? What type of housing is going to be provided, and what is the time schedule that it will be possible? Second, Sir I also want to know from him whether he is also aware that the Delhi Development Authority administration is full of scandals and corruption ? Are you going to improve the working of the DDA (what type of Development Authority you are developing, I do not know. But the present DDA needs scrupulous overhauling, to remove corrupt people, so that the poor and the middle class people do not suffer. Do not bother about the rich people's colonies and cooperative societies. They are all going on. But this is the urgent need of the Delhi population. What can you say of this?

श्री अब्दुल गफूर: हम तो इन्ही के डर से सब बातें बताना चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत से क्वेश्चन उसमें पूछ लिये । नम्बर एक जहां वैसे इलाके हैं वहां सर्विस एण्ड साइट, गवर्नमेंट की तरफ से जहां तक मुमकिन है किया जाता है ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकरणी : सर्विस फैसिलिटी ?

श्री अब्दुल गफूर : साइट सर्विस उसको नाम है । मान लिया जहां पर इस किस्म की आबादी है, उनको एक छोटा सा रास्ता बनाना है तो उनमें से 2--3 मकानों को डिमालिश कर देना होगा तो हम वह करके करते हैं इसलिये कि उनके रहन-सहन का तौर तरीका बदले । दूसरी बात कि वहां पर कम्युनिटी सेंटर भी खोले जाते हैं । मान लिया हर एक घर में नहाने का पानी नहीं है तो एक जगह 10--20 ... **(व्यवधान)**

SHRI A. G. KULKARNI: Mr Minister, please try to reply to my question. You are giving a rambling reply to all the questions on the earth.

SHRI ABDUL GHAFOOR : Your supplementaries are jumbled and it is very difficult to find out which I should reply. (*Interruptions*)

SHRI A.G. KULKARNI: The Minister is either confused, because my supplementary is not jumbled; I asked you a straight question. But I think...... (*Interruptions*)

अल्लाह आपको दिमाग दे, जरा बोलें ।

श्री अब्दुल गफ्फूर: एक चीज इनको बताना चाहता हूं शायद इसी पर ये खुश हो जायेंगे । इन्होंने कहा डी०डी०ए० ... **(व्यवधान)** अब पहले आप डी०डी०ए० को समझें कि यह क्या बला है । अब इसी को हम समझाते हैं हुजूर ... **(व्यवधान)**

SHRI K. MOHANAN: It is 'Delhi Destruction Authority'. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If you do like this, I will go to the next question.

श्री अब्दुल गफूर : माननीय मेम्बर को समझाता हूं । उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है । हम भी चाहते हैं कि इसका जवाब दिया जाये ताकि आप लोगों की समझ में आ जाये । Under the Central Act the D.D.A is under my department फिर क्या है इसके एक्स-आफिशियो चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं । लेफ्टिनेंट गवर्नर की सौ गाड़ी चलती है, जहां जाते हैं घेर लेते हैं कहते हैं कि इसको दुरुस्त कर दिया जाये तो आर्डर जाता है डी०डी०ए० के वाइस-चेयरमैन को कि डू इट । लेकिन न बजट का प्राविजन न कोई इसका मालिक, न कोई एक्जीक्यूटिव आफिसर ... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह : इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं ? इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी सरकार है ।